

राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद
शासन सचिवालय जयपुर

क्रमांक एफ 2(62) (3)ग्रावि-3/नरेगा/2009-10

जयपुर दिनांक

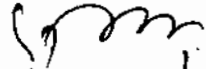
15/10/2009

परिपत्र

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा के लेखा वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 की वित्त विभाग द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से विशेष जांच करवाई गई। विशेष जांच प्रतिवेदन में योजना के क्रियान्वयन में निम्नानुसार गंभीर अनियमितताएं पाई गई :-

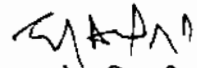
1. निधियों का गबन- एक ही कार्य को दो बार प्रथक्-प्रथक् योजनाओं में स्वीकृत करना, नगद अवशेष को रोकड़ पुस्तिका में अग्रेषित न कर धन का अपहरण, बिना बिल वाऊचर के राशि को रोकड़ पुस्तिका में इन्द्राज कर गबन, मस्टररोल में फर्जी प्रविष्टियां का इन्द्राज कर गबन, आदि।
2. कय में अनियमितताएं- सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध सामग्री का कय, स्टॉक रजिस्टर में सामग्री इन्द्राज का अभाव, बाजार दरों से अधिक दरों पर सामग्री कय, बिना मांग एवं आंकलन के सामग्री क्रय आदि।
3. मस्टररोल संधारण संबंधी अनियमितताएं- मस्टररोल में आवश्यक प्ररिविष्टियों का अभाव जैसे कि श्रमिक का नाम, जॉब कार्ड नं. आदि का इन्द्राज न करना, मस्टररोल का रोकड़ बही में दोहरी प्रविष्टि कर दोहरा भुगतान आदि।
4. कार्यों संबंधी अनियमितताएं- 90 प्रतिशत कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात कार्यों को निरस्त करना, कार्यों का लम्बे समय तक अपूर्ण रहना, कार्यस्थल पर प्रदर्शन बोर्ड का अभाव, एक ही प्रकृति के कार्य एक ही स्थान पर दो प्रथक्-प्रथक् योजनाओं में स्वीकृत किया जाना आदि।
5. अन्य अनियमितताएं- रोकड़ संधारण में अनियमितताएं स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करना, ऋणात्मक अवशेष के उपरान्त अनियमित कय, अंकेक्षण के क्रिया-कलाप के प्रति उदसीनता आदि।

संदर्भित वित्तीय अनियमितताओं के कम यह निर्देशित किया जाता है कि योजना के क्रियान्वयन में इस प्रकार की अनियमितता अन्य जिलों में भी हो सकती है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि योजनान्तर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग योजना के प्रावधानों के अनुसार ही हो तथा कय प्रकरणों, रिकार्ड संधारण, कार्यों की स्वीकृति तथा पूर्णता के क्रम में वित्तीय नियमों तथा योजना के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। योजना के क्रियान्वयन में धनराशि के दुरुपयोग आदि गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं तो इसकी तत्काल जांच करवाकर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमो पार्ट-I के नियम 20, 22 व प्ररिशिष्ट-3 के प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा अनियमितताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी कर्मचारियों/ अधिकारियों तथा पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे। उक्त आदेशों की पालना कठोरता से किया जाना सुनिश्चित करावे।


(राजेन्द्र माणवत)
आयुक्त, ईजीएस 14/10

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ को एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजि सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान को प्रेषित लेख है कि इस क्रम में आवश्यक निर्देश समस्त कार्यकारी एजेसियों को प्रसारित किये जावे।
4. समस्त अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी।


मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस